भारत पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए एसएससी में विकास वित्त और सहयोग

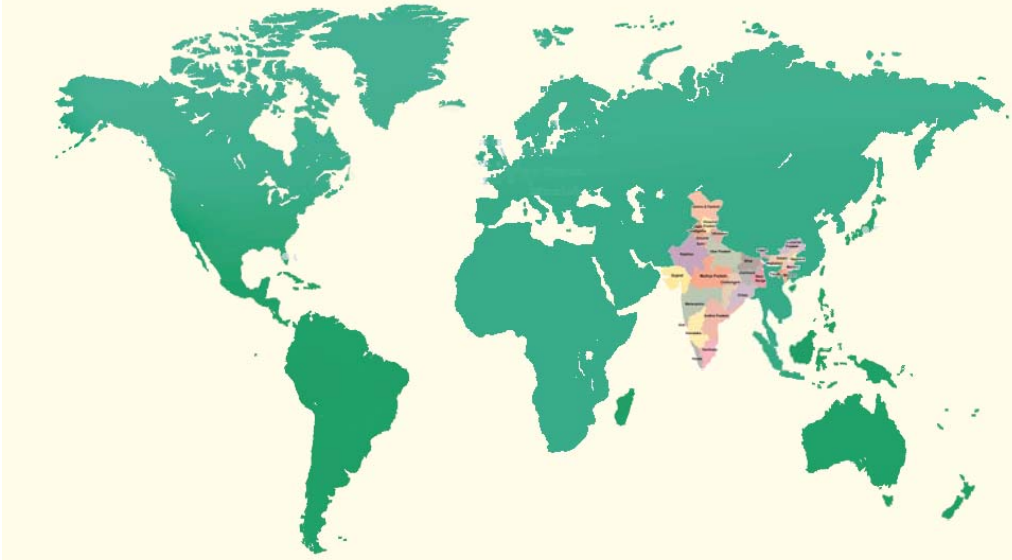

VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR
VANI

Brot für die Welt
Bread for the World – Protestant Development Service

वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)

भारत पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए एसएससी में विकास वित्त और सहयोग

लेखन : वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)

मार्च 2015

कॉपीराइट © वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया
इस पुस्तक की विषय वस्तु की प्रकाशक का उचित आभार प्रकट करते हुए पूर्ण या आंशिक रूप से पुनः मुद्रित किया जा सकता है।

सहयोग : ब्रैड फार दि वर्ल्ड

हिन्दी अनुवाद : डॉ. यश चौहान

प्रकाशक:
वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)
बीबी–5, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश इन्क्लेव 2,
नई दिल्ली 110 048
फोन : 011–29228127, 29226632
टेलिफैक्स : 011–41435535
ईमेल : info@vaniindia.org
वेबसाइट : www.vaniindia.org

मुद्रक:
ब्राईट डिजाईन फोकस # 987360495
ईमेल : bright.designfocus@gmail.com

VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR
VANI

Brot für die Welt
Bread for the World – Protestant Development Service

भारत पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए एसएससी में विकास वित्त और सहयोग

वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)
बीबी–5, पहली मंजिल, ग्रेटर कैलाश, इंक्लेव–2,
नई दिल्ली – 110 048
फोनः 011–29228127, 29336632
फैक्सः 011–41435535,
ईमेलः info@vaniindia.org
वेबसाइटः www.vaniindia.org

प्रस्तावना

हाल ही आर्थिक गिरावट, खाद्य और ऊर्जा संकटों से लगे महत्वपूर्ण आघातों के बावजूद सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। किन्तु सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की दिशा में यह प्रगति असमान है और विभिन्न देशों के बीच असमानताएं चिंता का महत्वपूर्ण कारण बनी हुई हैं। यह बढ़ती आर्थिक असमानता के दीर्घकालिक रूझान का एक अंग है जिसने विशेष रूप से निम्नतम विकसित देशों (एलडीसीज) को प्रभावित किया है। असमानताओं को समझना और उनसे निबटना सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने और 2015 के बाद समावेशपूर्ण संवृद्धि को पोषित करने की दिशा में प्रगति को तेज करने की कुंजी होगा।

2015 के बाद के विकास एजेंडा की रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया के बीच सहायता, जलवायु वित्त और स्थायित्वपूर्ण विकास को लेकर अनेक प्रकार के रुख उभर कर सामने आये हैं। सितंबर में न्यूयॉर्क में एक विशेष सत्र में स्थायित्वपूर्ण विकास लक्ष्यों को अपनाया जायेगा। यह सम्मेलन निर्धनता के विरुद्ध भूमंडलीय संघर्ष में एक नये युग को चिन्हित करेगा। इससे दो महीने पहले जुलाई में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एदिस एबाबा में विकास प्रक्रिया के लिए वित्त पर चर्चा करने के लिए एकजुट होगा। उसमें विकास कर्मियों का एक व्यापक हिस्सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (एसडीजीज) के कार्यान्वयन हेतु भुगतान करने के लिए एक भूमंडलीय वित्तीय योजना स्थापित करेगा। 17 प्रस्तावित एसडीजीज को हासिल करने के लिए खरबों डालर की जरूरत होगी। विशेष रूप से एसडीजी 17 को – जो अन्य 16 लक्ष्यों के लिए "कार्यान्वयन के साधनों" के संबंध में है – औद्योगीकृत सदस्य देशों द्वारा एफएफडी प्रक्रिया के अंतिम परिणाम के रूप में देखा गया है। एडिस में वित्त मंत्री, विकास बैंक, बहुराष्ट्रीय निगम, प्रमुख परोपकारी संस्थाएं और बाकी बहुपक्षीय प्रणाली यह निर्धारित करेंगे कि 2015 के बाद के विकास एजेंडा को किस प्रकार से कार्यान्वित करना है।

इसी संदर्भ में हमारा उद्देश्य दक्षिण–दक्षिण ढांचे के अंतर्गत विकास के लिए वित्त के मुद्दों पर नीति को लेकर विचार करना है। इस आलेख का उद्देश्य प्रभावकारी विकास सहयोग एजेंडा की और स्थायित्वपूर्ण विकास लक्ष्यों की उपलब्धि के संदर्भ में (दक्षिण–दक्षिण सहयोग के संदर्भ में) विकास के लिए वित्तपोषण के संबंध में भूमंडलीय संवाद की छानबीन करना है। यह माना जाता है कि एडिस सम्मेलन के दौरान समृद्ध देश उभरती अर्थव्यवस्थाओं से योगदान करने को कह सकते हैं। उदाहरण के लिए वे 0.7 प्रतिशत की अधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) के लक्ष्य की पूर्ति के लिए कह सकते हैं। यह सुविदित है कि अब ब्रिक्स देशों जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ विश्व आर्थिक शक्ति केंद्र भूमंडलीय दक्षिण में है। यह नीतिगत अंतर्दृष्टि बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं के साथ भारत की संलग्नताओं को और उसके विकास सहयोग को समझने का प्रयास करती है। इसके साथ ही यह भारत की विकास वित्त संस्थाओं पर और नव–निर्मित एनडीबी के संदर्भ में विकास सहयोग की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करती है। अंत में यह ब्रिक्स के भीतर सत्ता गतिशीलता, साथ ही दक्षिण एशिया में चीन के उभार पर और भारत के लिए इसके रणनीतिक और सुरक्षा निहितार्थों पर भी अंतदृष्टि प्रदान करती है।

मै इस अध्ययन को लिखने और अंतिम रूप देने के लिए डॉ. ज्योत्सना मोहन का आभार प्रकट करना चाहूंगा। साथ ही मैं इस पूरी परियोजना को सहायता प्रदान करने के लिए सुश्री एडा किरलीस, दक्षिण एशिया डेस्क, ब्रैड फार दि वर्ल्ड, प्रोटेस्टेंट डेवलपमेंट सर्विस का धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा।

हर्ष जेतली
मुख्य कार्य–अधिकारी

प्रस्तावना और पृष्ठभूमि

विकास के वित्तपोषण का मतलब क्या है?

2015 के बाद का एजेंडा एक विकसित होते और जटिल परिदृश्य से उभरने वाली नई चुनौतियों को हल करने का प्रयास करता है। इस संदर्भ में तीन मुख्य रूझान उभर कर सामने आ रहे हैं जो इस प्रकार हैं: पहला यह कि अधिकतर निर्धन लोग मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं और कुछ उच्च आय वाले देशों में भी रहते हैं। दूसरा यह कि यूरो क्षेत्र में संकट और मध्यपूर्व तथा उत्तर अफ्रीका में अशांति से यह पता चलता है कि विकसित और विकासशील, दोनों ही प्रकार के देशों को संवृद्धि और रोजगार जनन के कठिन कार्यों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, इन लम्बे संकटों से जुड़ी वित्तीय जरूरतों के परे अनेक पारंपरिक अनुदानकर्ताओं पर पड़े प्रभाव से उपलब्ध आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) में कमी आती है। तीसरे उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार, वित्त और अन्य संपर्क बढ़ रहे हैं। यह बदलाव नई और पारस्परिक रूप से लाभदायक साझेदारियों के अवसर प्रदान करता है।

रूपांतरणकारी विकास एजेंडा के वित्तपोषण के लिए यह आवश्यक होगा कि उपलब्ध संसाधनों का आधिकारिक और निजी क्षेत्रों से अतिरिक्त वित्त जुटाने के लिए प्रभावकारी और रणनीतिक रूप से उपयोग किया जाये। विकासशील देशों को कर प्रशासन को मजबूत बनाने, प्राकृतिक संसाधन राजस्व को बेहतर ढंग से उपयोग में लाने और अवैध वित्तीय प्रवाह पर अंकुश लगाने सहित घरेलू संसाधन लामबंदी में सुधार लाकर अपने विकास को वित्तपोषित करने के प्रयासों में तेजी लाने की जरूरत होगी। निजी क्षेत्र के वित्तपोषण को आकर्षित करने में – जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर निवेशों को बढ़ाने में – सार्वजनिक क्षेत्र की उत्प्रेरक भूमिका है।

विकास के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों की बढ़ती जटिलता:

सहायता परिदृष्य में विभिन्न प्रकार के देश और विशेषकर उच्च मध्य आय वाले देश प्रमुखता हासिल कर रहे हैं। इन देशों में ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) देश शामिल हैं जिनका भूमंडलीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)

में 25 प्रतिशत हिस्सा है और जहां विश्व की 40 प्रतिशत आबादी रहती है। इसके अलावा इन देशों में सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और तुर्की भी शामिल हैं। उनका बढ़ता हुआ ओडीए अन्य विकासशील देशों को बाहरी वित्तीय प्रवाहों के एक व्यापकतर रूझान का अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा है। ये नये साझेदार पारंपरिक अनुदानकर्ताओं द्वारा पूरी न की जा सकने वाली विकास जरूरतों की पूर्ति कर सकते हैं।

भूमंडलीय लक्ष्य हासिल करने के लिए निजी स्रोतों से संसाधन जुटाने की जरूरत होगी। इनमें एफडीआई, बैंक ऋण, पूंजी बाजार और निजी हस्तांतरण (उदाहरण के लिए प्रेषित राशियां) शामिल हैं। अधिकतर विकसित देशों के लिए एफडीआई पसंदीदा निजी वित्तीय साधन हैं क्योंकि इसमें उत्पादकता और संवृद्धि को मजबूत बनाने और अर्थव्यवस्था का विविधीकरण करने में सहायता प्रदान करने की क्षमता है। हालंकि अनेक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को पिछले दशक में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों तक बढ़ी हुई पहुंच हासिल हुई है, पर उपलब्ध वित्त और निवेश जरूरतों के बीच बढ़ता हुआ असामंजस्य नजर आता है। यह भूमंडलीय वित्तीय संकट की वजह से कमजोर बाजार स्थितियों की वजह से है। इंफ्रास्ट्रक्चर (अवसंरचना) के लिए दीर्घकालिक वित्त प्राप्त करना आवश्यक है और इसके लिए परियोजना तैयारी और ऐसी नीतियों तथा समझौतों की जरूरत होगी जो जोखिमों को कम कर सकें तथा दीर्घकालिक रूप से निवेशकर्ताओं के विश्वास को मजबूत बना सकें।

बदलते परिदृश्य में विकास में नये कार्य–पक्षः

ब्रिक्स, जी–20, निजी क्षेत्र और विकास फाउंडेशनें और अंतर्राष्ट्रीय कार्य–पक्ष बने रहेंगे और 2015 के बाद के परिदृश्य में उनकी प्रमुख भूमिकाएं हैं।

इसके अलावा, भूमंडलीय दक्षिण विश्व में एक प्रमुख शक्ति बन कर उभरा है, हालांकि विकसित और विकासशील देशों के बीच मूलभूत असमानताएं मौजूद हैं। नये विकास एजेंडा के अनेक महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। पहली बात तो यह है कि भूमंडलीय विकास संस्थाओं के अभिशासन ढांचे अभी राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं कर रहे हैं। इसमें तेजी से विकसित होते देशों द्वारा निभाई गई भूमिका भी शामिल

है। अगर भूमंडलीय दक्षिण को 2015 के बाद के एजेंडा में अपना विश्वास बनाये रखना है तो इस स्थिति को बदलना होगा और वह भी तेजी से बदलना होगा। दूसरे विकासशील देश, और वे देश भी जिन्होंने पिछले दशक में तीव्र संवृद्धि दर हासिल की है, अभी भी निर्धनता, अभाव, भूख, कुपोषण, जैंडर असमानता, निम्न शिक्षा स्तर और अपर्याप्त स्वास्थ्य देखरेख की समस्याओं से पीड़ित हैं। भूमंडलीय दक्षिण का उभार किसी भी रूप में उत्तर के उस ऐतिहासिक दायित्व को कम नहीं करता जो उसे आधोविकास (अंडरडेवलपमेंट) की विरासत और परिणामों पर पार पाने हेतु सहायता प्रदान करके निभाना है। आधिकारिक विकास सहायता के लिए अपनी सकल घरेलू आय का 0.7 प्रतिशत प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने में विकसित देशों की विफलता निराशाजनक है। इसी के साथ एकजुटता का नया और उत्साहजनक रूप स्वैच्छिक साझेदारी है जो बाहर से थोपे गये मानदंडों से मुक्त हो। नये विकास एजेंडा में दक्षिण–दक्षिण सहयोग के इस आवश्यक पहलू का सम्मान करना भूमंडलीय दक्षिण के लिए एक प्राथमिकता है।

इस समय तैयार किया जा रहा 2015 के बाद का स्थायित्वपूर्ण विकास एजेंडा सच्चे रूपांतरण का एक अवसर है।

यह निर्धनता के विरुद्ध और टिकाऊ भविष्य के लिए भूमंडलीय संघर्ष की दृष्टि से एक साधारण वर्ष था। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजीज) के निकट आते समापन ने पुनर्जीवित भूमंडलीय साझेदारियों की मदद से एक अधिक महत्वकांक्षापूर्ण उत्तराधिकारी एजेंडा की दिशा में भूमंडलीय कार्य को तेजी प्रदान की है। नया विकास एजेंडा 2015 में आयोजित किये जाने वाले इन तीन प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से उभरेगाः (i) जुलाई में विकास के लिए सहायता पर अदिस अबाबा में आयोजित किये जाने वाले तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन; (ii) भूमंडलीय स्थिरतापूर्ण विकास लक्ष्यों (एसडीजीज) को परिभाषित करने के लिए सितंबर में आम सभा का विशेष सम्मेलन (iii) पेरिस में दिसंबर में आयोजित होने वाला ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने पर नये समझौते के लिए सीओपी का 21 वां सम्मेलन।

नया उभरता हुआ 2015 के बाद का विकास एजेंडा एक ऐसे लक्ष्य की मांग करता है जो एमडीजीज के लिए उपयोग किये गये लक्ष्य से अधिक व्यापक, अधिक समग्रतापूर्ण और अधिक महत्वाकांक्षी हो।

एसडीजीज का उद्देश्य एडीजी लक्ष्यों के अधूरे कार्य को पूरा करना है। अत्यधिक निर्धनता को शून्य पर लाना और टिकाऊ विकास के तीनों लक्ष्यों – सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणगत – के मामले में प्रगति हासिल करना भी इसका उद्देश्य है। एमडीजीज का वित्तपोषण ओडीए प्रबंधन और आवंटन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। किन्तु टिकाऊ विकास लक्ष्यों (एसडीजीज) को हासिल करने के लिए अभूतपूर्व मात्रा में वित्त जमा करने की और कार्यान्वयन के अन्य संसाधन (एमओआई) जुटाने की जरूरत होगी। इसके लिए एक कहीं अधिक जटिल और समग्रतापूर्ण वित्तीय ढांचे की जरूरत होगी। इसके लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक और निजी स्रोतों की आवश्यकता पड़ेगी। कार्यान्वयन के अन्य साधनों में ऋण राहत और पुनर्गठन, व्यापार, टेक्नालॉजी हस्तांतरण, क्षमता विकास, भूमंडलीय अभिशासन में विकासशील देशों की और अधिक भूमिका जैसे मुद्दों को हल करने के लिए अधिक जटिल और सहबद्ध उपकरणों और साझेदारियों की जरूरत होगी।

विकास का अधिक राजनीतिक विजनः विकास नीतियों को ही नहीं, बल्कि सभी सार्वजनिक नीतियों की अंतः निर्भरता और सामंजस्य की छानबीन करना आवश्यक है।

इस आलेख का उद्देश्य टिकाऊ विकास लक्ष्यों (एसडीजीज) की उपलब्धि के संदर्भ में प्रभावकारी विकास सहयोग एजेंडा और विकास वित्तपोषण पर भूमंडलीय संवाद की छानबीन करना है (दक्षिण–दक्षिण सहयोग के संदर्भ में)।

यह विचार–विमर्श आदिस आबाबा में जुलाई 2015 में होने वाले इस विकास वित्तपोषण सम्मेलन से पहले हो रहा है जिसमें सरकारें 2015 के बाद टिकाऊ विकास लक्ष्य हासिल करने हेतु विकास वित्त जुटाने हेतु नई प्रतिबद्धताएं करेंगी। अमीर देश उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से अपनी वचनबद्धताओं के अनुरूप योगदान करने को कह सकते हैं। उदाहरण के लिए 0.7 प्रतिशत की आधिकारिक विकास

सहायता (ओडीए) के लक्ष्य की पूर्ति की पुष्टि करना और समय–सीमा निर्धारित करना।

इस दिशा में जेफरी सच के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क (एसडीएएफ)[1] ने सभी उच्च मध्यम आय वाले देशों के लिए (यानी उन देशों के लिए जिनकी प्रति व्यक्ति आय 12,476 डालर से अधिक है और जिनमें भारत तो नहीं, पर चीन और ब्राजील शामिल हैं) एक ठोस प्रस्ताव सामने रखा है कि वे अपनी राष्ट्रीय आय का 0.1 प्रतिशत विकास सहयोग के लिए प्रदान करें।[2] इस समय दस सबसे बड़ी यूएमआईसी अर्थव्यवस्थाओं द्वारा प्रदान किये गये विकास सहयोग के स्तरों के बारे में यह सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी है:

तालिका 1

सकल राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में विकास सहयोग

स्रोत : यूएन इकोसोक 2008, यूएनडीपी, 2013, ओईसीडी 2015

इनमें से दो देशों, वेनेजुएला और तुर्की में हो सकता है कि 0.1 प्रतिशत का लक्ष्य पूरा कर लिया हो। दक्षिण, अफ्रीका, ब्राजील और चीन में इस लक्ष्य को पूरा करने के रास्ते पर हैं। किन्तु तब भी अर्जेंटाइना, कोलंबिया, मैक्सिको और इस समूह के

[1] *http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2013/03/130316-Development-and-Climate-Finance-.pdf*
[2] *http://www.odi.org/comment/9370-emerging-economies-help-finance-development*

45 देश बच जाते हैं। इनमें से अधिकतर देशों के विकास सहयोग कार्यक्रम नहीं हैं। इन देशों को यह लक्ष्य पूरा करने हेतु अतिरिक्त संसाधनों का योगदान करना पड़ेगा।

यह लक्ष्य पूरा करने के लिए इन देशों को उपयुक्त समय देने से कार्यान्वयन की दरों को दूर करने में मदद मिलेगी। 0.7 प्रतिशत के लक्ष्य की पुष्टि 1970 में 1970 के दशक के अंत को अंतिम समय मान कर की गई थी। इसके अलावा देशों को आवश्यक नहीं कि विकास एजेंसियां स्थापित करनी पड़े। पर मामला जो भी हो सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) के 0.1 प्रतिशत का लक्ष्य अधिकतर यूएमआईसीज[3] के लिए वर्तमान स्थिति से अलग होने का एक महत्वपूर्ण बिन्दु होगा।

एसएससी में विकास वित्त पर भारत का रुख

पिछले दो दशकों में भारत की आर्थिक संवृद्धि की दृष्टि से देखें तो देश ने विशेषकर एशिया और अधिकाधिक रूप से अफ्रीका में निम्न आय वाले देशों को विदेशी सहायता प्रदान करने में अधिकाधिक रूप से प्रमुख भूमिका निभाई है। भारत सरकार विकास सहयोग को विदेश नीति के एक अभिन्न अंग के रूप में देखती है।

1990 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था उदारीकरण के दौर से गुजरी और मिश्रित, राज्य–नेतृत्व वाली अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी और बाजार–उन्मुख दृष्टिकोण की दिशा में बढ़ी। उसकी विदेश नीति अधिकाधिक रूप से भू–आर्थिक विचारों से प्रभावित थी और इसके साथ ही ये बढ़ती हुई महत्वकांक्षाएं भी थी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में उसके मत का अधिक महत्व होगा। भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित अनेक बहुपक्षीय मंचों पर उभरते हुए और विकासशील देशों के और अधिक प्रतिनिधित्व का बार–बार आवाहन किया है।

[3] *http://www.odi.org/comment/9370-emerging-economies-help-finance-development*

इस संदर्भ में यह नीति बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं और विकास सहयोग के साथ भारत की संलग्नता को देखने का प्रयास करती है। साथ ही यह भारत की विकास वित्तीय संस्थाओं और नये–नये निर्मित किये गये एनडीबी के संदर्भ में विकास सहयोग की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करती है। अंत में यह ब्रिक्स के भीतर सत्ता गतिशीलता और साथ ही दक्षिण एशिया में चीन के उभार और इससे भारत के लिए रणनीतिक और सुरक्षा निहितार्थों पर ध्यान केंद्रित करती है।

ओईसीडी के आकलनों के अनुसार, भारत का कुल रियायती विकास वित्त वर्ष 2012 के 1.1 अरब अमरीकी डालरों (ओईसीडी आकलन) की तुलना में वर्ष 2013 में 1.3 अरब अमरीकी डालर था। भारत ने वर्ष 2013 में बहुपक्षीय संगठनों के माध्यम से अपने विकास वित्त के 5 प्रतिशत (65 मिलियन अमरीकी डालर) का उपयोग किया।[4] विदेशी मंत्रालय (एमईए) के अंतर्गत विकास साझेदारी सुशासन (डीपीए) अनुदानों और भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटीईसी) का प्रबंधन करता है और साथ ही भारत के समस्त द्विपक्षीय विकास सहयोग का प्रबंधन करता है। वित्त मंत्रालय बहुपक्षीय सहायता का प्रबंधन करता है और एक्सिम बैंक द्वारा दिये गये रियायती ऋणों आदि की निगरानी करता है।

भारत के प्राथमिक साझेदार देश दक्षिण एशिया के उसके पड़ोसी हैं। वर्ष 2000 और 2010 के बीच भूटान को भारत के कुल विकास सहयोग का 49 प्रतिशत प्राप्त हुआ था। भारत के विकास सहयोग के मुख्य क्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा (हाइड्रोपावर) और सूचना प्रौद्योगिकी हैं।

वर्ष 2013 और 2012 में बहुपक्षीय संगठनों के माध्यम से भारत का विकास सहयोग विशेष कर इंटरनेशनल फंड फार एग्रिकल्चरल डेवलपमेंट (आईएफएडी) के माध्यम से उपलब्ध कराया गया था।

---

[4] *http://www.oecd.org/india/indias-development-co-operation.htm*

भारत में विकास वित्त के महत्वपूर्ण स्रोत

घरेलू संसाधनों की लामबंदी:

घरेलू संसाधनों में घरेलू, निगमित और सरकारी बचतें शामिल हैं। घरेलू संसाधन लामबंदी को प्रभावित करने वाले कुछ कारक इस प्रकार हैं – प्रति व्यक्ति आय का स्तर और संवृद्धि, समाज में व्यक्तियों की बचत, पसंद, वित्तीय इंटरमीडिएशन में विकास और विश्वास का स्तर जनसांख्यिक ढांचा और वित्तीय/मौद्रिक नीतियां। इन संसाधनों को उत्पादक कार्यों में निवेश में बदलना मूलभूत नियमों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इनमें बैंकिंग क्षेत्र के नियमनकारी और पर्यवेक्षणकारी (सुपरवाइजरी) ढांचे और सीक्योरिटीज और ब्रांड बाजार की गुणवत्ता तथा आकार सहित अनेक कारक शामिल हैं। इसके अलावा कानून और व्यवस्था की स्थिति, कुशल कार्यशक्ति की उपलब्धता, भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति आदि भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निर्मातों को प्रोन्नत करने से देश आयात की जरूरतों के भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं। निर्यात अक्सर नई टेक्नालॉजी, पूंजी वस्तुओं और कच्चे मालों के आयात के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।

अपने साथी ब्रिक्स देशों के विपरीत भारत में ऐसी कोई अकेली संस्था नहीं है तो राष्ट्रीय विकास वित्त की निगरानी कर सके। 1947 में आजादी प्राप्त करने के बाद भारत ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का राष्ट्रीयकरण किया और एक ऐसी राष्ट्रीय विकास रणनीति अपनाई जो औद्योगीकरण की प्रक्रिया में तेजी ला सके। अगले 50 वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक ने विकास वित्त संस्थाओं (डीएफआईज) की स्थापना की जिसका उद्देश्य देश की इंफ्रास्ट्रक्चर (अवसंरचना) जरूरतों को पूरा करना था। इस प्रयास के फलस्वरूप 30 राष्ट्रीय विकास वित्त संस्थाओं (डीएफआईज) की स्थापना की गई।

1990 के दशक में वित्त क्षेत्र में सुधारों के साथ ही राष्ट्रीय विकास वित्त संस्थाओं (डीएफआईज) के कार्य वातावरण में पर्याप्त बदलाव आया। निम्न–आपूर्ति वाली

निधियों की आपूर्ति को वापिस ले लिया गया और समय के साथ–साथ राष्ट्रीय विकास वित्त संस्थाओं (डीएफआईज) की मध्यवर्ती भूमिका समाप्त हो गई। पिछले दो दशकों में भारत में महत्वपूर्ण डीएफआईज को यूनिवर्सल बैंकों में बदलने की एक लहर देखी गई है।

आज भारत में 10 राष्ट्रीय डीएफआईज हैं जो अपने–अपने क्षेत्रों में वित्त, नियमन और पर्यवेक्षण की भूमिका निभाती है। इसके अलावा 40 राज्य–स्तरीय डीएफआईज हैं जो यही उत्तरदायित्व निभाती हैं, उप–राष्ट्रीय स्तर पर। ये डीएफआईज विशेष क्षेत्रों में दीर्घकालिक निवेश का वित्तपोषण करने में अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि डीएफआईज की संख्या घट रही है, पर बाकी राष्ट्रीय डीएफआईज से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता में पिछले 10 वर्षों में वृद्धि होती रही है।

हालांकि घरेलू इंफ्रास्ट्रक्चरल व्यय में पर्याप्त वृद्धि हुई है, पर भारत में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। 12 वीं पंचवर्षीय योजना (योजना (2012–17) के अनुसार देश को इस कमी को दूर करने के लिए एक ट्रिलियन डालर व्यय करने होंगे।[5] इस संदर्भ में भारत की डीएफआईज और साथ ही क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय संस्थाएं इस कमी को दूर करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

यहां तक कि संग्रह (1449490 करोड़) का उपयोग एक या दूसरे व्यय की भरपाई के लिए किया जा रहा है, पर देश के इंफ्रास्ट्रक्चरल (अवसंरचनात्मक) और विकास कार्य के लिए नहीं किया जा रहा है। विकास कार्य के संसाधनों से यानी 17.77 लाख करोड़ में से मात्र 1.35 लाख करोड़ का उपयोग नये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और वर्तमान सुविधाओं को उन्नत बनाने आदि के लिए किया जा रहा है। इसका मतलब है कुल आकलित राजस्व का मात्र 7.5 प्रतिशत[6]।

विदेशी वित्तीय संसाधनः

---

[5] *भारत सरकार, योजना आयोग, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्य उप–समूह, "बारहवीं पंचवर्षीय योजना की कार्यान्वयन अवधि में इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण जरूरतें और उसके स्रोत (2012–2017), http://planningcommission.gov.in /aboutus/committee/wg_sub_infrastructure.pdf.*

[6] *प्रसाद,सी.ए., सरकार कर राशि का उपयोग कैसे करती है, मार्च 2015, http://www.simplifiedlaws.com/how-does-the-government-spend-tax-money/#comment-1984629477*

विदेशी निवेश योग्य संसाधनों में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली से प्राप्त निधियां अतंर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों से प्राप्त निधियां, निगमित निकायों से प्राप्त निधियां (एफडीआई) और विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक जैसी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं से तथा द्विपक्षीय अनुदानकर्ता संस्थाओं से प्राप्त ओडीए शामिल है।

ब्रेटनवुड्स समझौतों के 44 मूल हस्ताक्षरकर्ताओं में से भारत भी एक है। इन समझौतों के फलस्वरूप इंटरनेशनल बैंक फार रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का गठन हुआ था। इसके साथ ही भारत 1956 में गठित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय कार्पोरेशन (आईएफसी) और 1960 में गठित "इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (आईडीए) का अंग भी है। आजादी के बाद भारी निवेश जरूरतों के प्रकाश में भारत ने हमेशा इन संस्थाओं के साथ अपने संबंध को उत्तर–दक्षिण संबंध के संदर्भ में देखा। इस संदर्भ में एक उधार प्राप्त करने वाले के रूप में भारत ने वित्तीय और गैर–वित्तीय दृष्टि से निम्नतम लागतों पर अधिक संसाधनों का आग्रह किया।[7] पर समय के साथ–साथ बहुपक्षीय संस्थाओं के साथ भारत की संलग्नता धीरे–धीरे कम होती गई है। इसकी वजह से नीतिगत बदलाव आये हैं। इसी के साथ इस तथ्य को देखने को लेकर अंतर्विरोध पैदा हुए हैं कि इस देश में विश्व की एक–तिहाई आबादी रहती है।

निम्नलिखित पैराग्राफ में भारत में विकास कार्यक्रमों में कुछ महत्वपूर्ण बहुपक्षीय संस्थाओं की भूमिका और योगदान के बारे में बताया गया है।

विश्व बैंक:

भारत विश्व बैंक के पांच में से चार घटकों का सदस्य है। ये इस प्रकार हैं–"इंटरनेशनल बैंक फार रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी), इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (आईडीए); इंटरनेशनल फिनांस कार्पोरेशन (आईएफसी) और मल्टीनेटरल इंवेस्टमेंट गारंटी एजेंसी (एमआईजीए)। भारत आईसीएसआईडी (यानी इंटरनेशनल सेंटर फार सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्पयूट) का सदस्य नहीं है।

---

[7] *सिंह, सुरेंद्र और मुकम्ब चेनाई, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं के साथ भारत का अनुभव, ब्रिक्स अंतदृष्टि आलेख, जीईजी, अफ्रीका*

भारत विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से (मुख्यतः आईबीआरडी और आईडीए के माध्यम से) निधियां प्राप्त करता रहा है।

भारत आईबीआरडी, आईडीए और आईएफसी का संस्थापक सदस्य है। भारत में विश्व बैंक की सहायता की शुरूआत 1948 में तब हुई थी जब एक कृषि मशीनरी परियोजना के लिए फंडिंग (वित्त) मंजूर की गई थी। भारत में विश्व बैंक रेसिडेंट मिशन की स्थापना 1957 में की गई थी। अगस्त 1956 में एड इंडिया कंसोर्टियम की पहली बैठक वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक के तत्वावधान में आयोजित की गई थी। भारत में आईएफसी का पहला निवेश 1.5 मिलियन अमरीकी डालर के साथ 1959 में किया गया। भारत जरूरी 1994 में एमआईजीए का सदस्य बना।[8]

ऋण

भारतः वित्त वर्ष के अनुसार वचनबद्धताएं (दस लाख डालरों में)

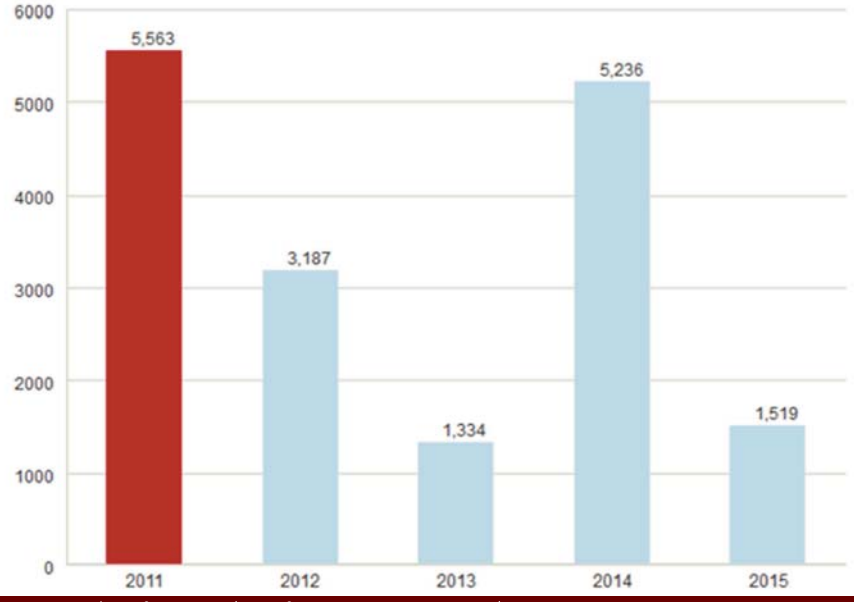

** इस राशि में आईबीआरडी और आईडीए वचनबद्धताएं शामिल हैं।*

[8] *भारत और विश्व बैंक समूह, http://finmin.nic.in/the_ministry/dept_eco_affairs/ MI/India_WB.pdf*

वित्त वर्ष 2013–2017 की अवधि के लिए विश्व बैंक समूह की देश साझेदारी रणनीति का पूर्ण लक्ष्य भारत में निर्धनता की स्थिति में कमी लाना है। यह लक्ष्य देश की 12 वीं पंचवर्षीय योजना (वित्त वर्ष 2013–2017) के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। नई रणनीति का एक मुख्य लक्षण निम्न आय वाले राज्यों में – जहां भारत के अनेक निर्धन और अभावग्रस्त लोग रहते हैं–महत्वपूर्ण बदलाव है। साथ ही यह संस्था की पहली देश रणनीति है जो निर्धनता में कमी लाने और निर्धनतम लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का विशेष लक्ष्य लेकर चलती है। इसमें सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वार्षिक रूप से 8.2 प्रतिशत की संवृद्धि की अपेक्षा की गई है जिसके अंतर्गत सभी राज्य ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकास की तुलना में अधिक तेजी से आगे बढ़ सकें। इसमें निर्धनता दर को दस प्रतिशत बिंदु तक कम करने की परिकल्पना की गई है। इसके साथ ही इस योजना का लक्ष्य स्कूलों में जेंडर संबंधी और सामाजिक अंतरों को कम करना है, शिशु मृत्युदर में कमी लाना है, और बालिकाओं और बालकों के अनुपात में धीरे–धीरे करके सुधार लाना है। विश्व बैंक की नई रणनीति अगले पांच वर्षों में हर वर्ष 3 अरब से 5 अरब अमरीकी डालर प्रदान की है। इसमें से 60 प्रतिशत सरकारी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को प्राप्त है। इसमें से आधा या 30 प्रतिशत निम्न आय वाले या विशेष वर्ग के राज्यों को जायेगा। यह पिछली रणनीति की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक है।

विश्व बैंक की भारत रणनीति एक ऐसे परिदृश्य की रूपरेखा प्रस्तुत करती है जिसमें भारत आर्थिक विकास की समावेशिता से सुधार ला सके। ऐसा सुधार जो सर्वोत्तम कार्य–प्रदर्शन करने वाले राज्यों ने हासिल किया है। इससे वर्ष 2030 तक आबादी की निर्धनता 5.5 प्रतिशत तक हो जायेगी जबकि इस निर्धनता का स्तर 2010 में 29.8 प्रतिशत था। अगर भारत को उसी प्रकार विकास करना है जिस प्रकार उसने संवृद्धि को समावेशपूर्ण बनाये बिना 2005 और 2010 के बीच किया था तो निर्धनता केवल 12.30 प्रतिशत कम होगा जबकि 33.6 प्रतिशत 2030[9] तक असहायता की सीमा से ऊपर रह जायेंगे।

[9] *http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/04/12/new-world-bank-group-strategy-to-help-india-achieve-its-vision*

ध्यान केंद्रित करने के मुख्य क्षेत्र

अगले पांच वर्षों में सीपीएस इन तीन मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी:

समेकन या एकीकरण; रूपांतरण और समावेश। इन तीनों का मुख्य विषय होगा – अभिशासन में सुधार; पर्यावरण को और अधिक स्थिर बनाना और जेंडर समानता।

एकीकरण:

भारत के व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर या अवसंरचना की जरूरतों को केवल सार्वजनिक निवेश से पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए यह रणनीति इंफ्रास्ट्रक्चर या अवसरंचना में सार्वजनिक और निजी निवेश, दोनों को सुधारने और प्रोन्नत करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। उदाहरण के लिए आर्थिक विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा क्षेत्र के और अधिक क्षमताएं विकसित करनी होंगी और साथ ही उसे जेनेरेशन (जनन), ट्रांसमिशन तथा वितरण की क्षमताएं भी तैयार करनी होंगी। बेहतर एकीकरण या समेकन से भारतीय राज्यों में एक अधिक संतुलित संवृद्धि संभव होगी और निम्न आय वाले राज्य अपने तेजी से बढ़ते पड़ोसियों के साथ जुड़ सकेंगे।

रूपांतरण:

यह प्रक्षेपित (प्रोजेक्टिड) या अनुमानित किया गया है कि वर्ष 2031 तक 60 करोड़ लोग भारत के शहरों में रह रहे होंगे। सुप्रबंधित शहरीकरण के असंख्य लाभ हो सकते हैं यह रणनीति शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार के लिए राष्ट्रीय, राज्य और नगर प्रशासनों के प्रयासों में मदद करेगी।

समावेश:

आर्थिक एकीकरण और ग्रामीण–शहरी रूपांतरण भारत की काफी बड़ी आबादी को लाभ प्रदान कर सकता है, बशर्ते कि मानव विकास और उन नीतियों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाये जो विकास को और अधिक समावेशपूर्ण बनाती हैं। विश्व

बैंक समूह पोषण नीति को और साथ ही पोषण में सुधार लाने वाली प्रणालियों और क्षमताओं को मजबूत बनाने में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करेगा। इसके अलावा वह शिक्षा के सभी स्तरों पर गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुख्यतः द्वितीयक और तृतीयक स्तर पर शिक्षा में सुधार लाने के सरकार के प्रयासों में सहायता प्रदान करेगा। अधिकारहीन और अभावग्रस्त बच्चों को शिक्षा प्रदान करने, माध्यमिक स्तर शिक्षा में लड़कियों को बनाये रखने और उच्चतर शिक्षा के द्वारा खोलने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जायेगा। इससे वित्त तक पहुंचने में सुधार आयेगा और अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाली 90 प्रतिशत श्रम शक्ति के सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाया जा सकेगा[10]

वर्ष 2014 में विश्व बैंक के निजी क्षेत्र घटक, आईएफसी ने भारत में मुख्य क्षेत्रों में 4.7 अरब का निवेश करने की वचनबद्धता की थी। ये क्षेत्र इस प्रकार हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर (अवसंरचना), टेलिकोम्स, ऊर्जा, शिक्षा, जल प्रबंधन और स्वास्थ्य देखरेख। भारत विश्व बैंक समूह का सबसे बड़ा सेवाग्राही (क्लाएंट) है। इस समूह ने इंटरनेशनल बैंक फार रिकंस्ट्रक्शन (आईबीआरडी) में 5.2 बिलियन डालर की इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन में 3.1 बिलियन डालर की और 16 परियोजनाओं में सीटीएफ द्वारा 0.1 बिलियन की वचनबद्धता की है।[11] (जुलाई 2013 से जून 2014)।

अपनी ओर से एशियाई विकास बैंक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर (अवसरंचना) विकास के लिए देश को 7 बिलियन डालर से लेकर 9 बिलियन डालर तक का योगदान करेगा; और साथ ही तकनीकी सहायता के लिए 30 मिलियन डालर का अतिरिक्त योगदान करेगा। इसके बावजूद बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं कार्यान्वित करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मंजूरियां मिलने में देरी, भूमि अधिग्रहण में देरी, पर्यावरण मंजूरी के मुद्दे और गुणवत्तापूर्ण मानव शक्ति का अभाव।[12]

---

[10] *http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/04/12/new-world-bank-group-strategy-to-help-india-achieve-its-vision*

[11] *http://www.worldbank.org/en/country/india/projects*

[12] *सिंह सुरेंद्र और मुकम्ब चेनाई, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं के साथ भारत का अनुभव ब्रिक्स अंतदृष्टि आलेख 1, जीईजी, अफ्रीका*

एशियाई विकास बैंक

भारत एशियाई विकास बैंक (एडीबी) का संस्थापक सदस्य रहा है और अब वह चौथा सबसे बड़ा अंशधारक है। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने भारत में अपने कार्यों की शुरूआत 1986 में की थी। और इसने वर्ष 1986–2014 के दौरान 31.3 बिलियन डालर के 189 ऋण मंजूर किये थे। 31 दिसंबर 2014 तक इसमें 11.5 बिलियन अमरीकी डालर के 86 संप्रभु (सोवरिन) ऋण शामिल थे।[13]

भारत में एडीबी के कार्यों के परिणामस्वरूप ग्रामीण सड़क सेक्टर 2 निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत बाथन में बारहमासी सड़कों का निर्माण किया गया जो कि भारत सरकार की "प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना" (पीएमजीएसवाई)[14] को पूरित करता है। ग्रामीण सड़कों के निर्माण से स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका जैसी सेवाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ी है जिससे निर्धनता में कमी लाने और जीवन स्तरों के विकास पर प्रभाव पड़ा है। 1986 में 2013 के बीच, एडीबी ने 31.5 अरब डालर के ऋण मंजूर किये थे। इनमें से 29.1 अरब डालर के ऋण सामान्य पूंजी संसाधन (ओसीआर) संप्रभु ऋण थे और 2.4 अरब डालर के ऋण गैर संप्रभु ओसीआर ऋण थे। (तालिका 2)

तालिका 2
भारत को मंजूर एडीबी ऋण (दस लाख डालरों में)

ऋण	1986-2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
ओसीआर सोवरिन	17,117.6	1,777.6	1,711.0	2,119.6	2,324.9	1,952.0	2,111.5
ओसीआर गैर–सोवरिन	592.0	705.0	100.0	...	548.0	238.0	248.4
योग	**17,709.6**	**2,482.6**	**1,811.0**	**2,119.6**	**2,872.9**	**2,190.0**	**2,359.9**

ए–योग में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के गैर–सोवरिन कार्य
स्रोतः एडीबी आकलन शामिल हैं।

[13] *एशियाई विकास बैंक और भारत, तथ्य शीट, http://www.adb.org/publications/india-fact-sheet*

[14] *पीएमजीएसवाई (प्राइम मिनिस्टर रूरल रोड प्रोग्राम) ग्रामीण संड़कों के विकास के लिए एक अग्रगामी कार्यक्रम है।*

चित्र–1

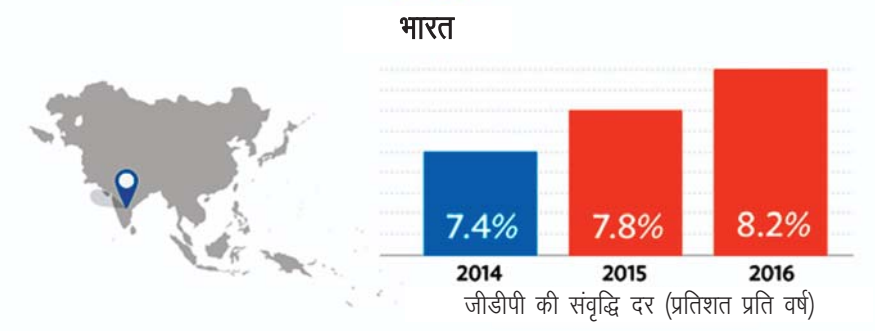

स्रोत : एडीबी आकलन [15]

भारत में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की सहायता में पिछले अनेक वर्षों में वृद्धि हुई है। इस सहायता से भारत सरकार को अपनी प्राथमिताएं तय करने में मदद मिली है। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की देश साझेदारी रणनीति (सीपीएस), 2013–2017 का उद्देश्य सरकार की 12 वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताओं में मदद करना है ताकि "अधिक तीव्र, अधिक समावेशपूर्ण और टिकाऊ संवृद्धि या विकास" हासिल किया जा सके। बहुपक्षीय विकास साझेदारों के साथ कार्य करने के सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) परियोजना डिजाइन और कार्यान्वयन में नवाचारों और कार्य के सर्वोत्तम तौर–तरीकों को आधार बनाता है।

भारत में एडीबी की रणनीतियां और प्राथमिकताएं

इंफ्रास्ट्रक्चर–चालित विकास के माध्यम से निर्धनता को कम करने के भारत के प्रयास में सहायता प्रदान करते हुए, एडीबी के भारत कार्यक्रम, सरकार की विकसित

[15] *http://www.adb.org/countries/india/economy*

होती प्राथमिकताओं और समावेशपूर्ण तथा टिकाऊ संवृद्धि पर अधिकाधिक ध्यान केंद्रित करते हुए, दृष्टि से, विकसित और परिपक्व हुआ है।

ऊर्जा, परिवहन और शहरी सेवाओं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों के लिए अपनी सहायता जारी रखते हुए, एडीबी अब इंफ्रास्ट्रक्चार वित्त के क्षेत्र में नवाचारपूर्ण कार्यों में संलग्न है और जल संसाधन प्रबंधन, कृषि व्यवसाय इंफ्रास्ट्रक्चर विकास तथा कौशल विकास में सुधार लाने हेतु कार्य कर रहा है।[16]

एडीबी सरकार के अधिक तीव्र, समावेशपूर्ण और टिकाऊ विकास के विजन में सहायता प्रदान कर रहा है और 1986 से ही एक विकास साझेदार है। शुरू में एडीबी की रणनीतियां सुधार एजेंडा की आरंभिक प्राथमिकताओं के अनुरूप विकसित की गई थीं। पिछले कुछ वर्षों में भारत का कार्यक्रम अपने सेक्टोरल, भौगोलिक और

चित्र 2: सेक्टर के अनुसार भारत को एडीबी के ऋण 1986–2013

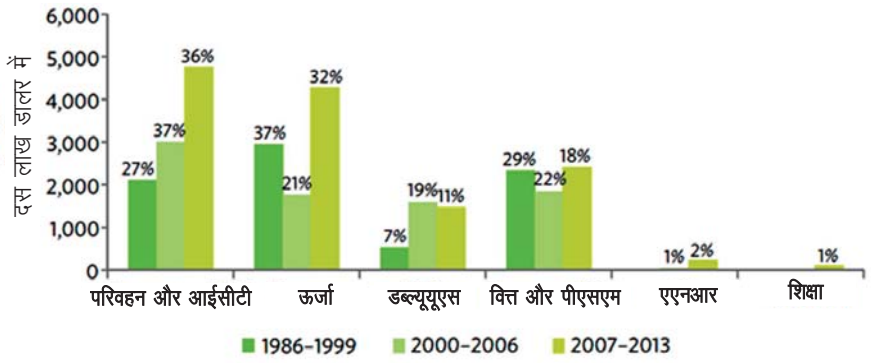

एएनआरः कृषि और प्राकृतिक संसाधन; आईसीटी = सूचना और संचार टेक्नालॉजी,
पीएसएम = सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन; डब्ल्यूएएन = जल और अन्य शहरी सेवाएं
नोटः डाटा स्तर पूरी मंजूर राशि में सेक्टर = वार अंश को दर्शाते हैं।

स्रोत : एडीबी आकलन

[16] *http://www.adb.org/countries/india/main*

विषयगत कवरेज की दृष्टि से विकसित और परिवक्व हुआ है। एडीबी भारत को ऋण और गैर–ऋण दोनों प्रकार के उत्पाद प्रदान करता है। इन उत्पादों में ऋण, तकनीकी सहायता (टीए), और अनुदान शामिल हैं। परियोजना और सेक्टर–विशिष्ट ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रभावकारी ज्ञान कार्यक्रम की सहायता से संस्थागत सुदृढ़ीकरण और क्षमता विकास भारत में एडीबी के कार्यों का अभिन्न अंग रहे हैं।[17]

एडीबी के पोर्टफोलियो में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विशिष्ट टीए परियोजनाएं और अनुदान शामिल हैं। टीए क्षमता विकास, बेहतर परियोजना तैयारी और कार्यान्वयन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) पहलकदमियों, और ज्ञान उत्पादों के लिए प्रदान की जाती है (चित्र 3)। वर्ष 2000–2013 के दौरान एडीबी ने संचयी आधार पर 218.5 मिलियन डालर की टीए परियोजनाएं मंजूर की थीं। भारत में एडीबी के कार्यों में अनेक विकास साझेदार सहायता प्रदान करते हैं जिसमें महिला सशक्तीकरण के लिए उद्यमिता, कृषि व्यवसाय मूल्य श्रृंखला में सुधार और जल उपयोगकर्ता एसोसिएशनों (डब्ल्यूयूएज) में असुरक्षित समूहों की भागीदारी को प्रोन्नत करना शामिल है। वर्ष 2000–2013 के दौरान भारत के लिए 17 परियोजनाएं और 33.1 मिलियन डालर के टीए अनुदान मंजूर किये गये। ब्रिटेन की संस्था "दि डिपार्टमेंट फार इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डीएफआईडी) भारत में वर्ष 2001 से एडीबी के साथ सहयोग करती रही है। भारत के लिए एडीबी – डीएफआईडी साझेदारी (2009–2014) ने कुल 22 मिलियन डालर का योगदान किया है और इससे असम, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा जैसे पिछड़े राज्यों में परियोजनाओं के लिए एडीबी की सहायता प्रदान करने में मदद मिली है।[18]

भारत में नागरिक समाज संगठनों के साथ एडीबी की साझेदारियां परियोजनाओं की डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए जमीनी स्तर का परिप्रेक्ष्य प्रदान करने में समुदाय

---

[17] विकास प्रभावकारित ब्रीफ, भारत, भारत – एडीबी, टिकाऊ और समावेशपूर्ण विकास के लिए साझेदारी, एडीबी प्रकाशन

[18] विकास प्रभावकारिता ब्रीफ, भारत, भारत – एडीबी, टिकाऊ और समावेशपूर्ण विकास के लिए साझेदारी, एडीबी प्रकाशन

चित्र–3 सेक्टर के हिसाब से तकनीकी सहायता परियोजनाएं – 2000–2013

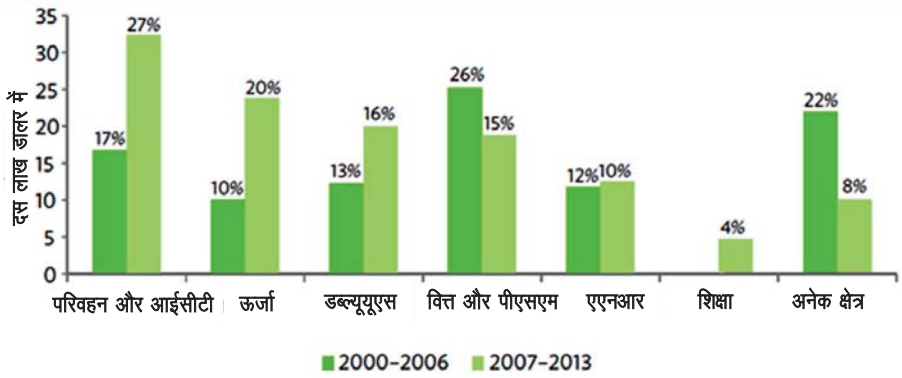

एएनआर कृषि और प्राकृतिक संसाधन
आईसीटी सूचना और संचार टेक्नालॉजी
पीएसएम सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन, डब्ल्यूयूएस जल और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तथा सेवाएं
टिप्पणी: डाटा तालिका एक समय के अंदर कुल मंजूरियों में विभिन्न क्षेत्रों के अंश को दर्शाती है। मल्टीसेक्टर में ज्ञान, क्षमता निर्माण, जेंडर आदि विषय शामिल हैं।

स्रोत : एडीबी आकलन

की भागीदारी और लामबंदी सुनिश्चित करने में और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने में काफी उपयोग रही हैं।

असुरक्षित और अलग-थलग पड़े समुदायों को स्कूलों, सेवाओं और बाजारों से जोड़ने वाली सड़कों में सुधार लाना भारत के विकास की कुंजी है।

एडीबी भारत में पिछले तीन दशकों से विकास पहलकदमियों में सहायता प्रदान कर रहा है। पर एडीबी की कार्यगत रणनीतियां और भौगोलिक क्षेत्र इन पिछले वर्षों के दौरान सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार बदला है। पहले एक दशक में एडीबी की पहलकदमियां मुख्यतः राज्यों में कुछ उपस्थिति के साथ राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं पर केंद्रित रहीं। आज स्थिति काफी बदल चुकी है और एडीबी की 23 भारतीय राज्यों में उपस्थिति है। बिजली, सड़क और जल आपूर्ति जैसे बुनियादी

इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं में एडीबी ने जो निवेश किया उससे करोड़ों लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है (तालिका–2)। ये लाभ दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, शहरी निर्धनों और महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभदायक रहे हैं क्योंकि इससे मुख्यधाराकरण (मेनस्ट्रीमिंग) के नये अवसरों के द्वार खुले हैं।[19]

वर्ष 2010–2013 के दौरान एडीबी ने भारत में 35,000 कि.मी. लंबी सड़कों का निर्माण और सुधार कार्य किया है। इनमें से 65 प्रतिशत सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और बाकी राजमार्ग हैं या ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों से जोड़ती हैं। 80 प्रतिशत से अधिक परिणाम पिछड़े राज्यों में देखे गये हैं।[20]

देश कार्य व्यवसाय योजना (2015–2017)[21] : भारत में देश कार्य व्यवसाय योजना (सीओबीपी), 2015–2017 का रणनीतिक जोर भारत देश साझेदारी रणनीति (सीपीएस) 2013–2017 के रणनीतिक लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के अनुरूप है।

सीओबीपी सीपीएस के तीन रणनीतिक स्तंभों में योगदान करता है जो इस प्रकार हैं: समावेशपूर्ण संवृद्धि या विकास; पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ विकास; और क्षेत्रीय सहयोग तथा एकीकरण।

सीपीएस 2013–2017 ने पहली बार भारत में मानव विकास के क्षेत्र में रणनीति तैयार की। एडीबी इस क्षेत्र में 100 मिलियन डालर की परियोजना के साथ मेघालय में मानव पूंजी विकास को सहायता प्रदान करते हुए प्रविष्ट हुआ था। यह परियोजना माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और तकनीकी तथा व्यावसायिक कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता, सुलभता और सुपुर्दगी में सुधार लाकर मेघालय में 60,000 युवाओं की रोजगार संभावना को बढ़ायेगी।

---

[19] *विकास प्रभावकारित ब्रीफ, भारत, भारत – एडीबी, टिकाऊ और समावेशपूर्ण विकास के लिए साझेदारी, एडीबी प्रकाशन*

[20] *विकास प्रभावकारित ब्रीफ, भारत, भारत – एडीबी, टिकाऊ और समावेशपूर्ण विकास के लिए साझेदारी, एडीबी प्रकाशन*

[21] *http://www.adb.org/documents/india-country-operations-business-plan-2015-2017*

तालिका 3
एडीबी के विकास के परिणामों को भारत में परिचालन का समर्थन

सेक्टर क्षेत्र	हासिल किये गये परिणाम (2010–2013)
परिवहन	
निर्मित की गई सड़कों का या ठीक की गई सड़कों का उपयोग बनाई गई	9,321.000
ठीक की गई सड़कें	35,000
एक्सप्रैस या नेशनल हाइवे	3,000
प्रांतीय, जिला और ग्रामीण सड़कें	32,000
ऊर्जा	
ग्रीन हाउस गैसों में कमी	837,000
बिजली की सुविधा से जोड़े गये नये परिवार	850,000
लगाई गई ऊर्जा जनन क्षमता (एमडब्ल्यू समकक्ष)	9,000
रिनिवल	200
लगाई गई और ठीक की गई संचरण लाइनें (कि.मी.)	7,000
लगाई गई और ठीक की गई वितरण लाइनें (कि.मी.)	66,000
जल और अन्य शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तथा सेवाएं	
नयी और उन्नत जल आपूर्ति वाले परिवार	3,611,000
ग्रामीण	416,000
शहरी	3,195,000
नये और उन्नत सेनिटेशन वाले परिवार	1,164,000
वेस्टवाटर उपचरण क्षमता में जोड़ी गई या सुधरी क्षमता (क्यूबिक मीटर प्रति दिन)	1,339,000
लगाये गये या उन्नत जल आपूर्ति पाइप (कि.मी. में दूरी	9,000
बाढ़ के जोखिम से कम पीड़ित परिवार	170,000
वित्त	
सूक्ष्म वित्त लेखा खोला गया/अंतिम ऋणी (संख्या)	491,000
महिला	442,000
पुरुष	49,000

tCO_2 = ton of carbon dioxide, km = kilometer, MW = megawatt.
Notes: Results are rounded off to the nearest 1,000. The above table provides information for closed and ongoing projects. Green highlighted indicators are gender indicators.

स्रोतः परियोजना पूरी होने की रिपोर्ट, त्रिपक्षीय बैठक ब्रीफिंग शीट; एडीबी परिणाम आउटलाइन

हाल की महत्वपूर्ण पहलकदमियां इस प्रकार हैंः राजस्थान शाश्वत ऊर्जा संचरण निवेश कार्यक्रम; कर्नाटक समाकलित शहरी जल प्रबंधन निवेश कार्यक्रम जिसका उद्देश्य जलवायु के अनुसार लचीलेपन को प्रोन्नत करना है; वर्ष 2013 में बादल फटने के कारण हुए विनाश के उत्तर में 200 मिलियन डालर की उत्तराखंड आपातकालीन सहायता परियोजना।

मौलिक आउटपुट्स के अलावा एडीबी ने अपने सेवाग्रहियों (क्लाएंट्स) की संस्थागत क्षमताएं विकसित करने में भी मदद की है। एडीबी विषयगत प्राथमिकताओं का मुख्यधाराकरण करने के अपने प्रयासों को जारी रखेगा जैसे कि जेंडर, जलवायु परिवर्तन, क्षमता विकास और निजी क्षेत्र विकास की प्रोन्नति। इसके अलावा बेहतर परियोजना प्रबंधन, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम कार्य तौर–तरीकों का आदान प्रदान और सफल परियोजनाओं का दुहराव और विस्तार। सरकार के साथ मिलकर एडीबी क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा और साथ ही अपनी पहलकदमियों को मजबूत बनायेगा। उनके अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता को आधार बनाते हुए विशेषकर पिछड़े राज्यों में अन्य विकास साझेदारों के साथ सहयोग को मजबूत बनाया जायेगा।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएफएफ)

भारत 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ में शामिल हुआ था और वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के मूल सदस्यों में से एक है। देश ने 20 अगस्त, 1994 को वर्तमान लेखा कनर्वेटेबिलिटी पर समझौते के "अनुच्छेद viii"[22] के दायित्वों को स्वीकार किया है। भारत आईएमएफ के विशेष डाटा प्रसार मानक में भी शामिल हुआ। इस समूह के देश मानदंडों का पालन करने और अपने डाटा तथा डाटा प्रसार के तौर–तरीकों के बारे में जानकारी देने के लिए वचनबद्ध होते हैं।

वित्तीय सहायता

भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संसाधनों का लगातार उपयोग करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के ऋण ने भारत को दो अवसरों पर भुगतान संतुलन की समस्याओं से निबटने में मदद की है। "1981–82 में भारत ने विस्तारित निधि सुविधा के अंतर्गत 3.9 अरब एसडीआर का ऋण लिया था, यह उस समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के इतिहास में सबसे बड़ा ऋण था। 1991–93 में भारत ने

[22] *अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समझौते पर लेख, http://www.imf.org/external/pubs/ ft/aa/#art8*

प्रबंध के अंतर्गत 2.2 अरब एसडीआर का ऋण लिया और 1991 में अनिवार्य वित्तीय सुविधा के अंतर्गत 1.4 अरब एसडीआर का ऋण लिया।[23]

आईएमएफ और भारत सरकार भारत में मार्च 2016 में एशिया की प्रगति पर एक उच्चस्तरीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मिलकर मेजबानी करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य संवृद्धि को तीव्र करने, आघातों से निबटने हेतु क्षेत्र में लचकीलापन निर्मित करने और आबादियों के बीच लाभों का अधिक व्यापक रूप से बंटवारा करने के तरीकों की छानबीन के लिए एशिया के नेताओं को एक मंच पर लाना है।[24] इसी के साथ आईएमएफ अतिरिक्त प्रशिक्षण पहलकदमियों और बढ़ी हुई तकनीकी सहायता के माध्यम से भारत में नीति क्षमता निर्माण में सहायता के लिए तैयारी कर रहा है।

भारत का अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग

जहां भारत आंतरिक रूप से पर्याप्त विकास वित्त का व्यय करता है, वहीं वह अनेक अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यकलापों में भी संलग्न है। पिछले 20 वर्षों में वह विश्व के सबसे बड़े अनुदाता सहायता प्राप्तिकर्ता से आगे बढ़कर विकास सहायता का सबसे बड़ा उभरता आर्थिक प्रदाता बन गया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता का बढ़ता हुआ दायरा पिछले कुछ वर्षों में भूमंडलीय समुदाय में भारत के व्यापक होते राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव को प्रतिबिंबित करता है।

आजादी के बाद के वर्षों में भारत की विकास सहायता की प्रकृति में भी बदलाव आया है। 1950 और 1960 के दशकों में देश की विकास सहायता में अधिकतर आर्थिक कार्य मंत्रालय (एमईए) द्वारा प्रदान किये जाने वाले अनुदान और ऋण शामिल होते थे। 1990 के दशक के आरंभ में भारत ने विकास सहायता का विस्तार करने के वैकल्पिक साधनों के लिए प्रयास किया। उसने लाइन्स ऑफ क्रेडिट (एलओसीज) की स्थापना की जिससे सरकार को निजी क्षेत्र के जरिये अधिक

[23] *http://www.imf.org/external/country/ind/rr/glance.htm*
[24] *https://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15118.htm*

संसाधन जुटाने और वित्त मंत्रालय के माध्यम से ब्याज दरों को सब्सीडाइज करने में मदद मिली। एलओसीज भारत की विकास सहायता का प्रमुख माध्यम बनी हुई हैं तथा अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमरीका में उसके विकास सहयोग का मुख्य घटक हैं। वे प्राप्तिकर्ता देशों के लिए सामानों और सेवाओं का आयात करना और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास तथा क्षमता–निर्माण के लिए परियोजनाएं हाथ में लेना सुगम बनाती हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत के एलओसीज के प्रमुख लाभार्थी अफ्रीकी देश रहे हैं; विकासशील देशों को आवंटित 1.1 बिलियन डालर में से 6.659 बिलियन डालर इन्हीं देशों को प्राप्त हुए हैं।[25]

भारत द्वारा प्रदान की जाने वाली विकास सहायता की बढ़ती राशि की वजह से एक केंद्रीकृत समन्वयन ढांचे की जरूरत स्पष्ट हो गई। देश के विदेशी निवेशों को सप्रवाही बनाने के लिए अंततः आर्थिक कार्य मंत्रालय (एमईए) के अंतर्गत 2012 में विकास साझेदारी प्रशासन की स्थापना की गई। भारत ने यह पहचान की है कि विकास साझेदारी साझेदार देश द्वारा चिन्हित जरूरतों पर केंद्रित होनी चाहिए और विकास साझेदारी प्रशासन की भूमिका तकनीकी और वित्तीय दोनों रूप में संभव अधिकतम आवेदनों पर विचार करने की होगी। इस समय विकास साझेदारी प्रशासन की तीन प्रभाग हैं: 1) डीपीए–1 का कार्य परियोजना मूल्यांकन और लाइन्स आफ क्रेडिट से संबंधित है; डीपीए–2 क्षमता निर्माण योजनाओं, विपदा राहत और भारत तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का कार्य देखता है और 3) डीपीए–2 परियोजना कार्यान्वयन का कार्य करता है। डीपीए के माध्यम से अपने विकास साझेदार देशों के साथ घनिष्ठ सहयोग से भारत सरकार स्थापना से लेकर पूर्ण होने तक सभी सहायता परियोजनाओं को प्रभावकारी और कार्यक्षम रूप से संचालित करने की अपेक्षा करती है।

विकास सहायता मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण–पूर्व एशिया है जो क्षेत्र में देश के पड़ौसियों की ओर निर्देशित है। भूटान इस समय भारत की वित्तीय सहायता का

[25] *सिंह सुरेंद्र और मुकम्ब चेनाई, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं के साथ भारत का अनुभव ब्रिक्स अंतदृष्टि आलेख1, जीईजी, अफ्रीका*

सबसे बड़ा प्राप्तिकर्ता है। भारत विकास सहयोग को समान विकास पथ वाले अन्य देशों के साथ अपने विकास अनुभवों को बांटने के एक साधन के रूप में देखता है। यह कहा जाता है कि इससे उसका भू–राजनीतिक प्रभाव बढ़ेगा और यह मुख्यतः रणनीतिक हितों से चालिक है। आपसी लाभ के सिद्धांत पर आधारित इस प्रकार की विकास सहायता का उपयोग भारत अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विशेषकर चीन से भारत को अलग रूप में प्रस्तुत करने के लिए करता है। भारत क्षेत्र में राशि के संवितरण की दृष्टि से चीन का मुकाबला नहीं कर सकता; इसलिए वह टेक्नालॉजी, औद्योगिक कृषि, शिक्षा और सूचना तथा संचार टेक्नालॉजियों के क्षेत्र में अपनी तुलनात्मक बढ़त का उपयोग करता है।

नया विकास बैंक–ब्रिक्स

ब्राजील में आयोजित छठे ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) सम्मेलन में आरंभ किये गये 100 अरब डालर के विकास बैंक का उद्देश्य विकासशील देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का वित्तपोषण करना है। ब्रिक्स ने अल्पकालिक लिक्विडिटी दबावों को रोकने में देशों की मदद करने के लिए 100 अरब मुद्रा आरक्षित पूल की स्थापना भी की है। यह बैंक शांघाई, चीन में आधारित होगा और भारत पहले छह वर्षों तक इसकी अध्यक्षता करेगा, इसके बाद पांच–पांच वर्षों के लिए ब्राजील और फिर रूस करेंगे। छठे ब्रिक्स सम्मेलन के अवसर पर पांच देशों के नेताओं ने यह घोषणा की।

बैंक 50 अरब की पूंजी से अपने कार्य की शुरूआत करेगा। यह राशि पांचों संस्थापक देशों के बीच समान रूप से विभाजित होगी। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश चीन का कहना था कि बैंक में योगदान के लिए सदस्य देशों की आर्थिक शक्ति को आधार बनाया जाना चाहिए – पर उच्चतर योगदान का अर्थ होगा उच्चतर नियंत्रण।[26] पर सघन विचार–विमर्शों में – जिन्होंने बैंक की स्थापना में दो वर्ष का

[26] *भारत ब्रिकस के 100 अरब डालर के नये विकास बैंक का नेतृत्व करेगा (16 जुलाई 2014)* http://www.ndtv.com/india-news/india-to-head-brics-100-billion-new-development-bank-588975

विलम्ब किया – भारत और ब्राजील ने दूसरों की तुलना में अधिक बड़ा अंश हासिल करने की चीन के प्रयासों से संघर्ष किया। पिछले वर्ष उभरते बाजारों से पूंजी के निर्गमन के बाद ब्रिक्स को समन्वित कार्रवाई करनी पड़ी। नया बैंक ब्रिक्स के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। ब्रिक्स देशों में विश्व की लगभग आधी आबादी रहती है और ये भूमंडलीय आर्थिक आउटपुट के एक–पांचयतें हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं।

बैंक 2016 से ऋण देने का कार्य आरंभ करेगा और अन्य देशों की सदस्यता के लिए भी खुला रहेगा, पर ब्रिक्स का पूंजी अंश 55 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। चीन–जिसके पास विश्व का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है– कंटिंजेंसी मुद्रा मूल में सबसे अधिक योगदान करेगा या 41 बिलियन डालर का योगदान करेगा। ब्राजील, भारत और रूस 18–18 अरब डालर का और दक्षिण अफ्रीका 5 अरब डालर का योगदान करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो चीन अपने आधे योगदान को, दक्षिण अफ्रीका दुगने और बाकी देश प्रदान की गई राशियों को मांग सकते हैं।

चुनौतियां और अवसर

भारत का आर्थिक और मानव विकास हाल के समय की सबसे महत्वपूर्ण भूमंडलीय उपलब्धि है। वर्ष 2005–2010 के बीच भूमंडलीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में भारत का हिस्सा 1.8 प्रतिशत से बढ़कर 2.7 प्रतिशत हुआ; और 5 करोड़ 30 लाख लोगों को निर्धनता के दायरे से बाहर निकाला गया। समय के साथ–साथ संवृद्धि (ग्रोथ) में भी तेजी आई है, भूमंडलीय संकट के परिणामों के बावजूद ऐसा हुआ है। पिछले दशक में, भारत की अर्थ व्यवस्था 7.6 प्रतिशत औसत वार्षिक दर से विस्तारित हुई है। निर्यात सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 21.5 प्रतिशत हैं। यह प्रतिशत 1990 के मुकाबले तीन गुना अधिक है; और विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों का अतः प्रवाह (इनफ्लो) इसका 1.6 प्रतिशत है।[27] भारत में भूमंडलीय रूप से मान्यता–प्राप्त अनेक कंपनियां दवा, उद्योग, इस्पात, स्पेस टेक्नालॉजी के क्षेत्र में काम करती हैं और ई–गवर्नेंस तथा सार्वजनिक सेवा प्रदायगी के उपयोग की दृष्टि से भारत विश्व में अग्रणी स्थान पर है।

[27] भारत के लिए 2013–17 की अवधि के लिए देश साझेदारी रणनीति, दि वर्ल्ड बैंक

इन रूपांतरणों के हिसाब से देखें तो भारत तेजी से विकसित होते राष्ट्रों के ऊपरी 10 पर्सेंटाइल में शामिल है और एक प्रमुख भूमंडलीय आवाज बन चुका है।

इस दृष्टि से भारत की मानव विकास प्रगति उल्लेखनीय रही है: 1947 और 2013 के बीच जीवन क्षमता दुगुनी हुई है। 1947 में जब यह 31 वर्ष थी तब 2012 में यह आगे बढ़ कर 65 वर्ष हो चुकी है। वयस्क साक्षरता दर में चार गुना वृद्धि हुई है। 1951 में यह 18 प्रतिशत थी जो 2011 में बढ़कर 74 प्रतिशत हो गई थी।

हालांकि भारत ने आर्थिक संवृद्धि की दृष्टि से अनेक ऊर्जाव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर कार्य किया है पर यहां निर्धनता में कमी लाने का स्तर अनेक पूर्वी और दक्षिण–पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं से काफी कम है।

"इसके अलावा 68.8 प्रतिशत भारतीय प्रति दिन 2 डालर से कम पर जीवन बिताते हैं। और साथ ही वे आर्थिक आघातों के मामले में फिर से निर्धनता की स्थिति में पड़ने का जोखिम उठाते हैं।"[28] बेरोजगारी के 1994 में 4.3 प्रतिशत से 2011 में 3.5 प्रतिशत तक घटने के बावजूद विशेषकर टेलिकम्यूनिकेशंस, वित्त, बीमा, परिवहन, रियल एस्टेट जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों में कौशल संबंधी अंतर काफी उच्च है। विनिर्माण क्षेत्र में नकारात्मक रोजगार, वर्ष 2005 और 2010 के बीच, विशेष रूप से चिंता का कारण रहा है। इतना ही नहीं, भारत के 57 प्रतिशत युवा इसी प्रकार की बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं।[29]

मानव विकास की दृष्टि से देखें तो अनेक महत्वपूर्ण लाभों का पता चलता है, पर भारत अनेक सहस्राब्दी लक्ष्य संकेतकों की दृष्टि से काफी पीछे है। इनमें शिशु मृत्युदर, मातृ मृत्युदर आदि शामिल हैं। भारत मानव विकास संकेतकों की दृष्टि से 187 देशों में 135 वें स्थान पर रहा है। बाल लिंग अनुपात में प्रतिकूल श्रम बाजार और निम्न–उत्पादक परिसंपत्तियों के मामले में जेंडर असमानताएं अभी भी मौजूद हैं। घटता हुआ भूमिगत जल स्तर, शहरी क्षेत्रों में पानी की कमी और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का बढ़ता आभाव, बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के निम्न तरीके ऐसी

---

[28] एडीबी 2014, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के मुख्य संकेतक, 2014, मनीला
[29] टीम लीज सेवाएं, भारतीय श्रम रिपोर्ट, 2007, मुम्बई

चुनौतियां हैं जिनके लिए दीर्घकालिक एकीकृत या समेकित उपायों की जरूरत होगी। इतना ही नहीं भारत के 57 प्रतिशत युवा किसी न किसी रूप में बेराजगारी का सामना कर रहे हैं।[30] मानव विकास की दृष्टि से भारत ने महत्वपूर्ण लाभ हासिल किये गये हैं, यह स्पष्ट है पर भारत अभी भी शिशु मृत्युदर, मातृ मृत्यु पर, स्वच्छता सुविधाओं के हिसाब से सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) संकेतकों से काफी पीछे हैं। भारत 2014 में 187 देशों में मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से 135 वें स्थान पर है।

इन कमियों या अंतरों को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर विकास वाणिजिक केंद्र और बेहतर रोजगार हेतू आर्थिक क्षेत्रों का नेटवर्क बनाने की जरूरत होगी। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि समग्र विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने की जरूरत होगी। इस संबंध में मुख्य चुनौती निजी क्षेत्र के निवेशों को लामबंद करने की है। 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के दौरान क्षेत्र के माध्यम से एक अरब डालर के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश का आधार निवेश जुटाने का उद्देश्य सामने रख कर चल रही है।[31] इसके लिए निवेश और प्रबंधन सुधार आकर्षित करने हेतु सार्वजनिक संस्थाओं की संस्थागत क्षमताओं का विस्तार करने की जरूरत है। सर्वोपरि यह है कि प्रभावकारी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हेतु नियमनों और व्यवसाय प्रक्रिया को सुवाही बनाने सहित ढांचागत सुधारों के विस्तार करने और उन्हें मजबूत बनाने की जरूरत है।

इस प्रकार से भारत की विकास वित्त रणनीति दो कारकों पर आधारित हैः 1) भारत को अपनी निर्धनता और उक्त चुनौतियों से लड़ने के लिए भारी मात्रा में निवेश की जरूरत है। 2) उसे न केवल एशियाई मंचों पर, बल्कि भूमंडलीय क्षेत्र में भी अगली आर्थिक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति का पुनः पुष्ट करते हुए विकास सहायता/वित्तीय अनुदानकर्ता के रूप में अपनी भूमिका को जारी रखना होगा। कालेधन को वापस देश में लाने हेतू गंभीर प्रयास करने से रिजर्व बैंक को अपने पास पर्याप्त विदेशी रिजर्व रखने में मदद मिलेगी। इस स्थिति से देश की अर्थव्यवस्था को बल प्राप्त होगा। "औद्योगिक निकाय एसोचैम द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार

[30] वर्ष 2011 में 0.6 वर्ष आयु समूह में प्रति 1000 लड़कों पर 914 लड़कियां थीं।
[31] विकास प्रभावकारिता ब्रीफ, भारत, भारत–एडीबी : टिकाऊ और समावेशपूर्ण विकास के लिए साझेदारी (2014), एडीबी प्रकाशन

लगभग 2 ट्रिलियन या 120 लाख करोड़ डालर का भारतीय धन विदेशों में पड़ा है जो कि लगभग हमारी अर्थव्यवस्था के आकार का है। एसोचैम द्वारा किया गया काले धन का आकलन देश के सकल घरेलू उत्पाद से अधिक है जो कि वर्ष 2013–14 में 114 लाख या 1.9 अरब डालर था।"[32]

करों की चोरी ऐसा अन्य क्षेत्र है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। भारत को हर वर्ष कर–चोरी की वजह से 14 अरब रुपए (314 अरब डालर) का नुकसान होता है। "दि ब्लैक इक्नॉमी इन इंडिया" के लेखक श्री अरुण कुमार का कहना है कि इससे भारत सड़क, बंदरगाहों और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निधियों से वंचित हो जाता है। सामान्य सरकारी कर राजस्व भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 18 प्रतिशत है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंकड़ों के अनुसार चार ब्रिक राष्ट्रों में सबसे कम है।[33] भारत को अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए और कड़ी मेहनत करनी होगी। वर्तमान आर्थिक स्थिति के अनुकूल होने – यानी तेल की निम्न कीमतें, मुद्रास्फीति में कमी और संवृद्धि में बढ़ती वसूली से इस उद्देश्य के लिए एक आदर्श मंच प्राप्त हुआ है। बजट सत्र में सरकार के लिए आर्थिक नीति की अकेली सबसे बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था में निवेश की दर को बढ़ाने के लिए एक दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करना है। आर्थिक सिद्धांत के सभी पहलू संवृद्धि और रोजगार जनन को तीव्र करने में निवेशों की भूमिका पर बल देते हैं। इस समय भारत की अर्थव्यवस्था को ये दो लक्ष्य हासिल करने हैं, उनके बीच किसी भी प्रकार की भिन्नता दूसरे से प्राप्त सकारात्मक लाभों को समाप्त कर देगी।

भारत के विकास क्षेत्र में विदेशी बहु–पक्षीय वित्तीय संस्थाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी के साथ नये विकास बैंक (ब्रिक्स) की दो महत्वपूर्ण अनिवार्यताओं को संतुलित करने में प्रमुख भूमिका होगी। इससे देश एनडीबी ढांचों के माध्यम से क्षेत्र के विकास में योगदान कर सकेगा और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर घाटे का वित्तपोषण कर सकेगा।

---

[32] *विदेशों में रखा गया काला धन 120 लाख करोड़ का है: एसोचैम (जून 20, 2014) http://profit.ndtv.com/news/economy/article-black-money-stashed-abroad-seen-at-rs-120-lakh-crore-assocham-545276*

[33] *http://www.bloomberg.com/bw/magazine/in-india-tax-evasion-is-a-national-sport-07282011.html*

वाणी के प्रकाशनों की सूची

- नागरिक समाज की जवाबदेही के सिद्धांत और व्यवहार (अंग्रेजी)
- स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए समर्थकारी वातावरण – एक भूमंडलीय अभियान (अंग्रेजी)
- स्वैच्छिक संगठनों में अंतर्राष्ट्रीय सुशासन के लिए मॉडल नीतियां
- स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए सुशासन पर एक हैंडबुक
- भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र की स्थिति (प्राइमर) (हिंदी और अंग्रेजी)
- सहायता प्रभावकारिता चर्चा में नागरिक समाज की संलग्नता
- स्वैच्छिक संस्थाओं और निजी क्षेत्र के बीच बदलती गतिशीलता (अंग्रेजी)
- सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं में स्वैच्छिक संस्थाओं को शामिल करना (अंग्रेजी)
- भारत के भूमंडलीय पदचिन्ह (अंग्रेजी)
- भारत की विकास सहयाताः रुझान, चुनौतियां और सीएसओज के लिए निहितार्थ (अंग्रेजी)
- जी–20 में भारत की भूमिकाः एक नागरिक समाज दृष्टिकोण (अंग्रेजी)
- धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और चुनौतियां (अंग्रेजी और हिंदी)
- महिलाओं के साथ काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और चुनौतियां (अंग्रेजी और हिंदी)
- स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका और योगदान (अंग्रेजी और हिंदी)
- जमीनी स्तर की स्वैच्छिक संस्थाओं की चुनौतियां – अध्ययन रिपोर्ट का प्राइमर (अंग्रेजी और हिंदी)
- जल और स्वच्छता के संबंध में स्वैच्छिक क्षेत्र की संस्थाओं की भूमिका और योगदान (अंग्रेजी और हिंदी)
- दलितों को लेकर कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और चुनौतियां
- शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, जल और स्वच्छता के विषयगत मुद्दों को लेकर काम करने में सीएसआर का योगदान (अंग्रेजी और हिंदी)
- राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति पर पुनर्विचार और राष्ट्रीय स्वैच्छिक कार्य नीति की जरूरत (अंग्रेजी और हिंदी)
- राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति पर पुनर्विचार और राष्ट्रीय स्वैच्छिक कार्य नीति का नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिंदी)
- भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए समर्थकारी वातावरण – एक अध्ययन रिपोर्ट (अंग्रेजी व हिन्दी)
- भारत में भ्रष्टाचार और अभिशासन – वर्तमान स्थिति और आगे की प्रक्रिया नीतिगत सार (अंग्रेजी व हिन्दी)
- बहिष्कृत लोगों को शामिल करना – भारत में समावेशपूर्ण संवृद्धि सुनिश्चित करना नीतिगत सार (अंग्रेजी व हिन्दी)
- वित्तीय समावेश की आलोचनात्मक समीक्षा – भारत पर ध्यान केंद्रित करते हुए जी–20 के देश नीतिगत सार (अंग्रेजी व हिन्दी)
- भारत में सतत विकास – समीक्षा और आगे की प्रक्रिया नीतिगत सार (अंग्रेजी व हिन्दी)

बैड फार दि वर्ल्ड का परिचय

Brot für die Welt

Bread for the World – Protestant Development Service

प्रस्तावना

ब्रैड फार दि वर्ल्ड भूमंडलीय रूप से सक्रिय संस्था है जो जर्मनी में प्रोस्टेंट चर्चों की राहत और विकास एजेंसी है जो पूरे विश्व में कार्य करती है। यह संस्था विश्व के लगभग 100 देशों में निर्धनों की जीवन स्थितियों में सुधार लाने के लिए कार्य करती है। इस संस्था के कार्यों में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं – खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा का विस्तार, मानव अधिकारों, आदि के प्रति रूझान।

व्यापक मार्गनिर्देश

हमारी दुनिया, ईश्वर का निर्माण है। ईश्वर हमें प्यार करती है। और हम ईश्वर की अपेक्षाओं के अनुसार ही एक न्यायपूर्ण यानी अन्याय से रहित विश्व बनाने के लिए कार्य करते हैं। ब्रैड फार दि बर्ल्ड एक ईसाई भूमंडलीय समुदाय का अंग है।

कार्य

"ब्रैड फार दि वर्ल्ड" भूमंडलीय दक्षिण के देशों में अपना ध्यान केंद्रित करता है। उनकी परियोजनाओं का एक उद्देश्य स्थानीय लोगों और चर्च संबंधी साझेदार संगठनों के साथ घनिष्ठ रूप से काम करना है। लाबीइंग, सार्वजनिक संबंधों के माध्यम से यह संस्था राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करती है।

वाणी का परिचय

वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी) स्वैच्छिक संस्थाओं का एक शीर्ष निकाय है। वर्ष 1988 में स्थापित यह संस्था स्वैच्छिक क्षेत्र के प्रोन्नतिकर्ता/संरक्षरक और उसकी सामूहिक आवाज के रूप में कार्य करती है।

VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR
VANI

वाणी का आधार

- भारत के 25 राज्यों में फैली 10000 स्वैच्छिक संस्थाएं हैं।
- यह स्वैच्छिक क्षेत्र के संबंध में प्रकाशनों, शोध, लेखों और जानकारी का एक संसाधन केंद्र है।

लक्ष्य

- एक मंच में रूप में स्वैच्छिकवाद को बढ़ावा देना और स्वैच्छिक कार्रवाई के लिए जगह बनाना।
- एक नेटवर्क के रूप में भारत में स्वैच्छिक कार्रवाई का एक सचमुच राष्ट्रीय एजेंडा तैयार करने के लिए क्षेत्र के साझे मुद्दों और सरोकारों को एकीकृत करना। इसके अलावा वाणी बदलाव के एकजुट और टिकाऊ आंदोलन को मजबूत बनाने की दिशा में भारतीय स्वैच्छिक क्षेत्र के विभिन्न प्रयासों और पहलकदमियों के बीच संपर्क बनाती है।
- एक एसोसिएशन के रूप में; मूल्य आधारित स्वैच्छिक कार्रवाई और विशेषकर अपने सदस्यों के बीच दीर्घकालिक टिकाऊपन को पोषित की दिशा में कार्य करना।

कार्य के क्षेत्र

- स्वैच्छिक क्षेत्र में सुशासन के तौर–तरीकों को बढ़ावा देना
- नेटवर्कों को मजबूत बनाना
- स्वैच्छिक क्षेत्र की स्वतंत्र आवाज को रूप प्रदान करना
- स्वैच्छिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाली नीतियों और कानूनों के संबंध में शोध और पैरवी करना।

वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)
बीबी–5, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश 2, नई दिल्ली 110 048
फोन : 011–29228127, 29226632, टेलिफैक्सः 011–41435535
ईमेलः info@vaniindia.org,
वेबसाइटः www.vaniindia.org